बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 23 ● अंक: 204 ● नई दिल्ली ● वीरवार 14 अगस्त 2025 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 8

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

राजधानी में स्वतंत्रता दिवस और जन्माष्टमी पर ड्राई डे, आबकारी विभाग ने जारी किया आदेश

दिल्ली । दिल्ली सरकार ने स्वतंत्रता दिवस और जन्माष्टमी के मौके पर राजधानी में ड्राई डे का एलान किया है। 15 और 16 अगस्त को सभी शराब दुकानें, बार, रेस्टोरेंट, होटल और क्लब बंद रहेंगे। एक्साइज विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। यह कदम राष्ट्रीय पर्व पर शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया है। एक्साइज विभाग के आदेश के मुताबिक, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस और 16 अगस्त को जन्माष्टमी के कारण शराब की बिक्री, सर्विंग और स्टोरेज पर पूरी रोक रहेगी। यह पाबंदी सभी रिटेल शराब दुकानों, बार, रेस्टोरेंट, होटल और क्लबों पर लागू होगी। हालांकि, कुछ चुनिंदा होटल जो लाइसेंस प्राप्त हैं, वे अपने मेहमानों को कमरे में सर्व कर सकते हैं, लेकिन सार्वजनिक जगहों पर नहीं। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है.

मतदाता हितैषी है मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया, सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी

नई दिल्ली ।

बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर से सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण में मतदाताओं से मांगे गए दस्तावेजों की संख्या 11 है, जबकि मतदाता सूची के सारांश पुनरीक्षण में 7 दस्तावेजों पर विचार किया जाता था। यह दर्शाता है कि यह मतदाता हितैषी है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के लिए मतदाता के पास 11 दस्तावेजों का विकल्प है, जबकि पहले किए गए संक्षिप्त पुनरीक्षण में सात दस्तावेज मांगे गए थे, इससे यह साफ दिखता है कि प्रक्रिया मतदाताओं के लिए अनुकूल है।

इससे पहले न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने चुनावी राय बिहार में विशेष पुनरीक्षण (एसआईआर) कराने के चुनाव आयोग के 24 जून के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ताओं की इस दलील के बावजूद कि आधार को स्वीकार न करना अनुचित था, लेकिन अन्य दस्तावेजों के विकल्प भी दिए गए थे, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रक्रिया वास्तव में सबको साथ में लेकर चलने वाली है। पीठ ने कहा, राय में पहले किए गए संक्षिप्त पुनरीक्षण में दस्तावेजों की संख्या सात थी और एसआईआर में यह 11 है, जो दिखाता है कि यह मतदाता के लिए ठीक या उचित है। हम आपकी दलीलों को समझते हैं कि आधार को स्वीकार न करना ठीक नहीं है, लेकिन दस्तावेजों की अधिक संख्या वास्तव में समावेशात्मक है। शीर्ष अदालत ने कहा कि मतदाताओं को सूची में शामिल 11 दस्तावेजों में से कोई एक जमा करना जरूरी था।

सिंघवी की दलील

याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने इस बात से असहमति जताई। उन्होंने कहा कि दस्तावेजों की संख्या भले ही यादा हो, लेकिन उनका कवरेज सबसे कम है। उन्होंने मतदाताओं के पास पासपोर्ट की उपलब्धता का उदाहरण दिया। सिंघवी ने कहा कि बिहार में यह केवल एक से दो प्रतिशत है। राय में स्थायी निवासी प्रमाण पत्र देने का कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने कहा, अगर हम बिहार की आबादी के पास दस्तावेजों की उपलब्धता देखें, तो पता चलता है कि कवरेज बहुत कम है।

36 लाख पासपोर्ट धारकों का कवरेज ठीक दिखाई देता है

पीठ ने कहा कि राय में 36 लाख पासपोर्ट धारकों का कवरेज ठीक दिखाई देता है। न्यायमूर्ति बागची ने कहा, अधिकतम कवरेज सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न सरकारी विभागों से फीडबैक लेने के बाद आमतौर पर दस्तावेजों की सूची तैयार की जाती है।

विकास कार्य करते समय पर्यावरण की रक्षा करना जरूरी: उच्चतम न्यायालय

नई दिल्ली । उचतम न्यायालय ने बुधवार को तेलंगाना सरकार को कांचा गाचीबोवली वन स्थल के समग्र पुनरुद्धार के वास्ते एक ''अच्छा प्रस्ताव'' पेश करने के लिए छह सप्ताह का समय दिया और कहा कि राय सरकार को काटे गए पेड़ों को फिर से लगाना होगा। प्रधान न्यायाधीश बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा कि वन क्षेत्र को बहाल किया जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने कहा कि वह विकास के खिलाफ नहीं है, लेकिन पर्यावरण की रक्षा की जानी चाहिए। पीठ ने मामले की सुनवाई छह सप्ताह बाद के लिए स्थगित करते हुए कहा, समय-समय पर न्यायालय कहता रहा है कि हम विकास के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन यह सतत विकास होना चाहिए। विकास संबंधी गतिविधियां करते समय, पर्यावरण और वन्य जीवन के हितों का ध्यान रखा जाना चाहिए तथा क्षतिपूर्ति के उपाय सुनिश्चित किए जाने चाहिए। यदि सरकार ऐसा कोई प्रस्ताव लेकर आती है तो हम उसका स्वागत करेंगे। तेलंगाना सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा कि राय सरकार पूरे प्रस्ताव पर समग्र रूप से विचार कर रही है, जिसमें पर्यावरण और वन्यजीवों के हितों को विकास कार्यों के साथ संतुलित करने का प्रयास किया जा रहा है। शीर्ष अदालत ने 15 मई को कहा था कि हैदराबाद विश्वविद्यालय के निकट पेड़ों की कटाई प्रथम दृष्टया पूर्व नियोजित प्रतीत होती है। अदालत ने तेलंगाना सरकार से कहा था कि वह इसे बहाल करे अन्यथा उसके अधिकारियों को जेल हो सकती है। प्रधान न्यायाधीश ने कहा था कि यह सरकार पर निर्भर है कि वह जंगल को बहाल करे या अपने अधिकारियों को जेल भेजे। कांचा गाचीबोवली वनक्षेत्र में वनों की कटाई की गतिविधियों पर स्वतः संज्ञान लेते हुए, उचतम न्यायालय ने तीन अप्रैल को अगले आदेश तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। न्यायालय ने पेड़ों की कटाई के लिए जल्दबाजी में की गई कार्रवाई के लिए 16 अप्रैल को तेलंगाना सरकार को फटकार लगाई थी और निर्देश दिया था कि यदि वह चाहती है कि उसके मुख्य सचिव को किसी भी गंभीर कार्रवाई से बचाया जाए, तो उसे 100 एकड़ वन-रहित भूमि को बहाल करने के लिए एक विशिष्ट योजना प्रस्तुत करनी होगी।

कांस्टीट्यूशन क्लब चुनाव रिजल्ट : निशिकांत दुबे बोले, सोनिया गांधी का वोट देने आना दिखाता है कि

नई दिल्ली । दिल्ली के कांस्टीट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के चुनाव में बिहार के सारण सीट से बीजेपी के सांसद राजीव प्रताप रूडी ने जीत दर्ज की. उन्होंने सचिव पद के चुनाव में बीजेपी के ही नेता संजीव बालियान को हराया. माना जा रहा है कि रूडी को यादातर विपक्षी सांसदों को वोट मिला. क्लब के 11 कार्यकारी सदस्यों के पद के लिए 14 सदस्य मैदान में थे. इसमें रूडी के पैनल से जीत दर्ज की. इस चुनाव में बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे संजीव बालियान का खुले तौर पर समर्थन कर रहे थे. रूडी की जीत के बाद उन्होंने कहा कि संसदीय क्लब के चुनाव में मैं संजीव बालियान के साथ था, हूं. यह चुनाव बालियान के जीवन का ऐतिहासिक चुनाव है, इसने उनकी ताकत को दिखाया. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और सोनिया गांधी का क्लब के चुनाव में वोट देने आना उनकी जीत है. झारखंड के गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तत्कालीन सांसद और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जयप्रकाश अग्रवाल ने भी जब 2005 तथा 2010 का चुनाव रुडी के खिलाफ लड़ा था तो सोनिया गांधी या उनके मंत्रिमंडल के कोई भी सदस्य वोट देने नहीं आए थे. संसदीय क्लब की गरिमा बढ़ाने के लिए संजीव बालियान को बधाई तथा राजीव प्रताप रूडी को जीत की शुभकामनाएं. राजीव प्रताप रूडी पिछले करीब 25 सालों से कांस्टीट्यूशन क्लब के सचिव पद पर काबिज हैं. उन्होंने मंगलवार-बुधवार की रात को आए रिजल्ट पर कहा, मैं शायद 100 से अधिक वोटों से जीता हूं. और अगर इसे 1000 वोटरों से गुणा किया जाए, तो यह संख्या 1 लाख तक पहुंच जाती है. यह मेरे पैनल की जीत है. सभी अपनी-अपनी पार्टी से उठे और आकर वोट डाला. मेरे पैनल में कांग्रेस, सपा, तृणमूल कांग्रेस और निर्दलीय सांसदों के लोग थे. मुझे पिछले दो दशकों की मेहनत का परिणाम मिला है. कांस्टीट्यूशन क्लब के चुनाव में केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे सहित विभिन्न दलों के प्रमुख नेताओं ने वोट किया. अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान और पूर्व सांसदों सहित कुल 1,295 मतदाताओं में से करीब 690 मत पड़े. क्लब के पदाधिकारियों के चुनाव में यह अब तक का सबसे अधिक मतदान है. लोकसभा अध्यक्ष इस क्लब के पदेन अध्यक्ष होते हैं. लेकिन क्लब के कार्यकारी कामकाज में सचिव की महत्वपूर्ण भूमिका होती है.

पहलवान सुशील कुमार की जमानत रद्द, सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते के अंदर आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया

नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के एक मामले में पहलवान सुशील कुमार की जमानत रद्द कर दी है। कोर्ट ने उन्हें एक हफ्ते के अंदर आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है। ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार पर पहलवान सागर धनकड़ की हत्या का मामला दर्ज किया गया था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने उन्हें जमानत दे दी थी। पहलवान सुशील कुमार मामले में शिकायतकर्ता की वकील जोशीनी तुली ने कहा, आज सुशील कुमार को दी गई जमानत एक त्रुटिपूर्ण आदेश होने के कारण रद्द कर दी गई। इसीलिए पीड़ितों के पिता अशोक धनखड़ की अपील पर उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया गया है। हमने उस आदेश को इस आधार पर चुनौती दी थी कि वह एक त्रुटिपूर्ण आदेश था। यह कानूनन सही नहीं था, क्योंकि सुशील कुमार ने जब भी अंतरिम जमानत ली थी, तब गवाहों से छेड़छाड़ की थी। मुख्य गवाह ने मामले का समर्थन किया था। घटना का वीडियो फुटेज भी मौजूद था, इसलिए आज यह अपील स्वीकार कर ली गई। सुशील कुमार जब भी अंतरिम जमानत पर बाहर आए, उन्होंने घायल गवाहों सहित सभी सरकारी गवाहों से छेड़छाड़ की। इसीलिए वे सभी निचली अदालत के समक्ष अपने बयानों से मुकर गए। मुकदमा अभी भी चल रहा है। निचली अदालत में कई सरकारी गवाहों से पूछताछ होनी बाकी है।

हत्या मामले में किया गया था गिरफ्तार

सुशील कुमार पर संपत्ति विवाद में 4 मई, 2021 को दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम की पार्किंग में जूनियर पहलवान सागर धनखड़ और उनके दोस्तों पर जानलेवा हमला करने का आरोप है। हमले में घायल सागर ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। पुलिस ने इस मामले में सुशील कुमार को गिरफ्तार किया था।

क्या है पूरा मामला?

पूरा मामला पूर्व जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन सागर धनखड़ की हत्या से जुड़ा है। पहलवान सुशील कुमार ने साथियों के साथ मिलकर 5 मई को रात में सागर की पिटाई की थी। बाद में सागर की मौत हो गई थी। इसके अलावा चार और पहलवान भी जख्मी हुए थे। आरोप पत्र में 13 आरोपियों को नामजद किया गया है। दिल्ली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, गैर इरादतन हत्या, आपराधिक साजिश, अपहरण, डकैती, दंगा समेत अन्य अपराधों में प्राथमिकी दर्ज की थी। मामले से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें सुशील और उसके दोस्त मिलकर कुछ लोगों की पिटाई कर रहे थे।

धूल चेहरे पर थी और आप आईना साफ करते रहे...राहुल पर बीजेपी का तंज, कहा- हर हार के बाद नए बहाने ढूंढती है कांग्रेस

नई दिल्ली । भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने बुधवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के वोट चोरी के दावे पर कटाक्ष करते हुए कहा कि हर हार के बाद कांग्रेस नए बहाने ढूंढती रहती है। उन्होंने कहा कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव हारते देख कांग्रेस अन्य विपक्षी दलों के साथ मिलकर झूठे आरोप लगाने में जुट गई है। ठाकुर ने भाजपा मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अगर किसी के नेतृत्व में 90 बार चुनाव हारने का रिकॉर्ड है, तो वह राहुल गांधी के नेतृत्व में है। पार्टी के भीतर भी राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठते हैं। अपना हमला जारी रखते हुए ठाकुर ने कहा कि जब वे चुनाव हार जाते हैं, तो कभी ईवीएम पर प्रश्नचिन्ह खड़ा करते हैं, या वोटर्स पर ठीकरा फोड़ते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पहले कहा कि ईवीएम मशीन के साथ हेराफेरी होती है, ईवीएम बैन करो, बैलेट पेपर लाओ। फिर कहा ईवीएम को रिमोटली हैक किया जा सकता है। फिर कहा वीवीपैट 100 प्रतिशत चेक सुनिश्चित करो। कांग्रेस ने आत्मचिंतन नहीं किया, लेकिन ईवीएम से लेकर संवैधानिक संस्थाओं तक पर आरोप लगाते रही। अब बिहार चुनाव हारता हुआ देख पहले ही विपक्षी दलों के साथ मिलकर झूठे आरोप लगाने में जुटी है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि 1952 से अगर हम शुरुआत करें तो, कांग्रेस और सीपीआई ने मिलकर संविधान निर्माता, एक संत जैसे नेता डॉ. भीमराव अंबेडकर जी को चुनाव हरवाया। चुनावी भ्रष्टाचार की नींव कांग्रेस ने पहले चुनाव 1952 में ही रख दी थी। उन्होंने कहा कि आप

रिकॉर्ड चेक कीजिए, 74,333 वोट खारिज किए गए जबकि अंबेडकर जी मात्र 14,561 वोट से हारे थे। कांग्रेस ने तो संविधान निर्माता, एक दलित नेता को पहले चुनाव में ही निपटाने का काम किया। आप कल्पना कीजिए, जिन्होंने संविधान बनाया था, उसी को कांग्रेस परिवार ने चुनाव में धांधली कर हरा दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप रिकॉर्ड देखें, तो उन्होंने 74,333 वोट रद्द कर दिए, जबकि वह सिर्फ 14,561 वोटों से हारे। कांग्रेस ने संविधान निर्माता के साथ ही धोखाधड़ी की। यह वोट भ्रष्टाचार का एक स्पष्ट उदाहरण है। भाजपा नेता ने कहा कि इस परिवार और पार्टी का शुरू से चलन रहा है कि चुनाव हारते हो तो चुनाव आयोग पर, मतदाताओं पर या चुनाव आयोग की कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दो। इंदिरा गांधी ने तो कहा था, मतदाता मूर्खों का टोला हैं। राजीव गांधी जब चुनाव हारे तो उन्होंने बैलेट पेपर पर ठीकरा फोड़ दिया। राहुल गांधी के पिता जी कहते थे कि वोटिंग मशीन से चुनाव करवाओ और राहुल गांधी कहते हैं कि बैलेट पेपेर से चुनाव करवाओ। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि 5 बजे के बाद बहुत वोट बढ़ गए थे। 5 बजे से पहले 58 लाख वोट प्रतिघंटा पड़े थे, और 5 बजे के बाद 32.5 लाख वोट प्रतिघंटा पड़े थे। तो ये स्पष्ट है कि राहुल गांधी के आंकड़े भी झूठे हैं और वो भी झूठे है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जब कांग्रेस ऐसे वोट चोरी का आरोप लगाती है, तो उसका एक ही एजेंडा साफ नजर आता है...। घुसपैठियां वोट बैंक को बचाना कैसे है। एक वर्ग के वोट बैंक के लिए कैसे लड़ाई लड़नी है। राष्ट्र की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कैसे करना है। सच्चे-पक्के देशवासियों के वोट को नीचा कैसे दिखाना है। उन्होंने तंज भरे लहजे में कहा कि कल कुछ कांग्रेस के लोग कह रहे थे कि राहुल गांधी और विपक्ष के नेताओं ने बवंडर खड़ा किया... बवंडर नहीं गलती है... मैं राहुल जी को यही कहूंगा- धूल चेहरे पर थी और आज आईना साफ करते रहे।

कैसे बटी फौज, खजाना, बग्घी और हाथी?

'विभाजन की विभीषिका' इन दिनों पूरे देश में चर्चा का केंद्र है। लगभग सभी नगरों में इस 'विभीषिका' पर आधारित सेमिनार, नाट्य प्रस्तुतियां और अन्य विचार गोष्ठियां हो रही हैं। इस अवसर पर यह जानना अत्यंत दिलचस्प है कि इन्हीं दिनों 79 वर्ष पूर्व क्या-क्या घटा? 14 अगस्त 1947 को विभाजन के बाद नया देश पाकिस्तान बना था। जब धर्म के नाम पर देश के टुकड़े हुए तो सबसे मुश्किल काम था चल-अचल संपत्तियों का बंटवारा। विभाजन के दौरान दोनों के देशों के बीच सैनिक व सैन्य संपत्तियां, खजाना, शाही वाहन, कार्यालय फर्नीचर, स्टेशनरी आइटम यहां तक कि कलम और पेन-पेंसिल तक का बंटवारा हुआ था। देश इस वर्ष 79वां स्वतंत्रता दिवस का जश्न मना रहा है। इस तारीख से एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 धर्म के नाम पर देश के टुकड़े हुए तो सबसे मुश्किल काम था विभिन्न संपत्तियों का बंटवारा। यह बंटवारा कहीं-कहीं हास्यास्पद भी हो गया था। फौज, खजाना, बग्घी और हाथी को कैसे बांटा गया? जॉयमनी नाम की हथिनी को लेकर क्यों विवाद हुआ था। अंग्रेजों का राज और भारत-पाकिस्तान का विभाजन होना तय हो गया था। तब एक ब्रिटिश वकील सर सिरिल रैडक्लिफ को नई सरहद तय करने का काम दिया गया। इसी के साथ भौगोलिक विभाजन पूरा हो गया। अब सवाल यह था कि फौज, खजाना और सांस्कृतिक वस्तुओं का बंटवारा कैसे किया जाए। 16 जून 1947 को पंजाब विभाजन समिति का गठन किया गया। इसका काम था- वित्त, सेना और वरिष्ठ प्रशासनिक सेवाओं के विभाजन के साथ ही उनके कार्यालय और उपकरणों का बंटवारा। हालांकि, बाद में इस समिति का नाम विभाजन-परिषद कर दिया गया था जिसमें सरदार वल्लभभाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद और मुहम्मद अली जिन्ना भी शामिल थे। 14 अगस्त 1947 को पुरानी भारतीय सेना को बांटने का आदेश आ गया। ब्रिटिश भारतीय सेना का यह आखिरी आदेश था। सैनिकों से कहा गया कि वह अपनी मर्जी से भारत या नए बने राष्ट्र पाकिस्तान को चुन सकते हैं। इसमें भी एक शर्त रखी गई थी। एजाज पटेल की किताब 'सट्टलस ऑफ पैशन' के मुताबिक, शर्त यह थी कि पाकिस्तान का कोई भी मुस्लिम भारतीय राष्ट्र में और भारत का कोई गैर-मुस्लिम पाकिस्तान के सशस्त्र बलों में शामिल नहीं हो सकता। ब्रिटेन के नेशनल आर्मी म्यूजियम की रिपोर्ट के मुताबिक, विभाजन के बाद दो तिहाई जवान भारत को मिले और एक तिहाई पाकिस्तान चले गए। इस तरह 260000 जवानों ने भारतीय सेना और करीब 140000 ने पाकिस्तान को चुना था। पाकिस्तान को चुनने वालों में ज्यादातर मुस्लिम थे। इस रिपोर्ट के अनुसार, 98 फीसदी मुस्लिम सैनिकों ने मुल्क के तौर पर पाकिस्तान को चुना था जबकि सिर्फ 554 मुस्लिम अधिकारियों ने ही भारत में रहने का फैसला किया था। विभाजन से भारतीय सेना में करीब 36 फीसदी मुसलमान थे, जो घटकर 2 फीसदी रह गए। इनमें ब्रिगेडियर मुहम्मद उस्मान, ब्रिगेडियर मुहम्मद अनीस अहमद खान और लेफ्टिनेंट कर्नल इनायत हबीबुल्लाह जैसे कुछ अधिकारी भी शामिल थे, जिन्होंने भारत को अपना वतन चुना था। प्रोफेसर यास्मीन खान की किताब 'द लॉन्ग पार्टिशन एंड द मेकिंग ऑफ मॉडर्न साउथ एशिया' में लखनऊ के एक सैनिक गुलाम अली का जिक्र है। लखनऊ के एक सैनिक गुलाम अली कृत्रिम अंग बनाते थे। विभाजन के वक्त वह पाकिस्तान की मिलिट्री वर्कशॉप में थे। उनको लखनऊ वापस जाने से मना कर दिया और पाकिस्तान की सेना में शामिल कर लिया गया था। पाकिस्तानी सेना ने 1950 में गुलाम अली को यह कहकर निकाल दिया कि तुम भारत के नागरिक हो। जब वह भारत लौटे तो उन्हें पाकिस्तानी सैनिक मानकर बिना परमिट के सीमा पार करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। 1951 में अली को जेल से रिहा कर पाकिस्तान भेज दिया। अली ने छह साल तक दोनों देशों की जेल और रिफ्यूजी कैंपों में काटे। इसके बाद उन्हें पाकिस्तान में एक मुसलमान सैनिक माना गया और इस आरोप में जेल भेज दिया गया कि वह हिंदू कैदियों के कैंप में रह रहा था। सेना के बंटवारे के बाद दूसरी बड़ी चुनौती यह थी कि धन का बंटवारा कैसे किया जाए। विभाजन परिषद ने तय किया था कि एक ही केंद्रीय बैंक एक साल तक दोनों देशों में सेवाएं संचालित करेगा। 31 मार्च, 1948 तक दोनों देश मौजूदा सिक्के और मुद्रा को जारी रखेंगे। 1 अप्रैल से 30 सितंबर, 1948 के बीच पाकिस्तान नई मुद्रा पेश करेगा लेकिन पुरानी करेंसी भी वैध रहेगी। वैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नोट पाकिस्तान सरकार की मुहर के साथ वहां सालों-साल चलते रहे। दस्तावेज बताते हैं कि बंटवारे में पाकिस्तान को कुल 75 करोड़ रुपये दिए गए थे। भारत ने समझौते के मुताबिक, 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को 20 करोड़ रुपये दे दिए। बंटवारा होते ही पाकिस्तान की ओर से कबायलियों के भेष में आए सैनिकों ने कश्मीर में हमला किया। इससे नाखुश भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल ने दो-टूक कह दिया था कि कश्मीर पर प्रस्ताव के बिना पाकिस्तान को कोई भुगतान नहीं होगा। महात्मा गांधी तब इससे नाराज हो गए। उनका कहना था, समझौते के मुताबिक पाकिस्तान को 75 करोड़ रुपये और दिए जाएं। इसके लिए वह अनशन पर बैठ गए। ऐसे में पटेल की आपत्तियों के बावजूद तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को मजबूरन 15 जनवरी 1948 को पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपये देने पड़े थे। मजेदार बात यह है कि दोनों देश दावा करते हैं कि आज भी एक-दूसरे पर उनका पैसा बकाया है। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2022-2023 से पता चलता है कि पाकिस्तान पर भारत का 300 करोड़ रुपये का कर्ज है। वहीं, 2014 में पाकिस्तान के स्टेट बैंक ने कहा था कि भारत पर उसका 560 करोड़ रुपये बकाया है। विभाजन के दौरान दोनों देशों में चल-अचल संपत्तियों को लेकर खूब हंगामा हुआ था लेकिन सबसे ज्यादा खींचतान वायसराय की घोड़ागाड़ी एवं बग्घी के लिए हुई थी।

पुस्तक 'फ्रीडम ऐट मिडनाइट' के मुताबिक, वायसराय के पास ठाठ से सजी सोने और चांदी से बनी 12 बग्घी थीं। इनमें से छह बग्घी सोने और छह चांदी की थीं। जिन पर शानदार सजावट थी और लाल मखमली गद्दियां लगी थीं। भारत के वायसराय और शाही मेहमानों को इन्हीं में बिठाकर राजधानी में घुमाया जाता था। समस्या ये थी कि बग्घियों के सेट को तोड़ना ठीक नहीं था। ऐसे में तय किया गया कि एक देश को सोने की और दूसरे देश को चांदी की बग्घी दे दी जाए। दोनों देश सोने की बग्घी लेने पर अड़े रहे। कई दिनों तक बहसबाजी हुई लेकिन कोई फैसला नहीं हो पाया। फिर तय हुआ कि सिक्का उछाल कर फैसला कर लिया जाए। तब वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के एडीसी लेफ्टिनेंट कमांडर पीटर होज ने अपनी जेब से चांदी का सिक्का निकाला और हवा में उछाल दिया।

इस दौरान पाकिस्तानी सेना के उस वक्त नए-नए नियुक्त हुए कमांडर मेजर याकूब खां और भारतीय सेना के कमांडर मेजर गोविंद सिंह भी खड़े थे। विभाजन से पहले दोनों वायसराय के बॉडीगार्ड थे। सिक्का खनखनाता हुआ गिरा तो तीनों देखने लगे तभी मेजर गोविंद सिंह खुशी से चिल्ला उठे, सोने की बग्घियां भारत की हुईं। अन्वेषा सेनगुप्ता के शोध पत्र 'वेकिंग अप डिवाइडिंग एसेट्स ब्रिटिश इंडिया एंड पाकिस्तान इन टाइम्स ऑफ पार्टिशन' के मुताबिक, संपत्ति के बंटवारे के दौरान बंगाल के वन विभाग के स्वामित्व वाले एक हाथी जॉयमनी को लेकर भी रस्साकशी हुई थी। दरअसल, उस वक्त हाथी जॉयमनी की कीमत एक स्टेशन वैगन (लग्जरी कार) के बराबर थी। तय हुआ था कि पश्चिम बंगाल को वाहन मिलेगा और पूर्वी बंगाल को जॉयमनी। विभाजन के वक्त जॉयमनी पश्चिम बंगाल के मालदा में थी।

सम्पादकीय...

सोया हाथी जाग गया, अब नहीं रुकेगा

नौ अगस्त से हमारे देश की आजादी के पर्व की शुरुआत हो जाती है और आप सब आजाद भारत के आजाद विचारों के लोग हैं। इस तिरंगे के नीचे आप सब अपने-अपने क्षेत्र में आजादी का जश्न मना रहे हैं और मैं भी कलम की आजादी का जश्न मना रहा हूं, अब आइए आर्थिक आजादी की बात करते हैं। हमारे प्यारे भारत को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद हुए इस साल 78 साल हो जाएंगे। इन वर्षों में निश्चय ही हमने बेपनाह तरक्की की है। हम भारतीयों ने दुनियाभर में अपनी छाप छोड़ी है। तरक्की का वो कोई रास्ता नहीं बचा है जिस पर हम न चल रहे हों, तो स्वाभाविक है कि जलने वाले जलेंगे और हमारी तरक्की की राह में कांटे भी बिछाएंगे। हमारे आर्थिक संसाधनों पर उनकी लोभी नजर रहेगी। विश्व व्यापार जैसे संगठनों को लकवा मार चुका है। वे किसी की रक्षा के काबिल नहीं रह गए हैं, तो सवाल है कि मौजूदा स्थितियों से हम आखिर कैसे निपटें? इस वक्त पूरी दुनिया अमेरिकी टैरिफ में उलझी हुई है और हम इससे अछूते नहीं हैं, बल्कि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले देशों में हैं, जब मैं यह कॉलम लिख रहा हूं तो अमेरिकी टैरिफ 25 की जगह 50 प्रतिशत हो चुका है। यानी भारत 100 रुपए का सामान अमेरिका को निर्यात करता है तो उस पर वहां 50 रुपए टैक्स लग जाएगा। जाहिर है, भारतीय सामान अमेरिका में महंगा हो जाएगा और मांग कम हो जाएगी। कुल भारतीय निर्यात में अमेरिका की हिस्सेदारी 18 प्रतिशत है इसलिए हम निश्चय ही इस टैरिफ से प्रभावित होने जा रहे हैं। इस बिंदु पर आकर भारत की आर्थिक आजादी का सवाल खड़ा हो जाता है क्योंकि अमेरिका हमारी आर्थिक आजादी को नियंत्रित करना चाहता है। मैं मानता हूं कि भारत की आजादी की दौड़ को पचा पाना सबके बस का काम नहीं है और वो हर क्षेत्र में हमारी आजादी को रोकना चाहेंगे। मुझे हाल ही का एक उदाहरण याद आता है। हमारे जो उद्योगपति आज तेजी से बढ़ रहे हैं उनमें अंबानी हैं, अडानी हैं, सज्जन जिंदल हैं, टाटा, बिड़ला और कई अन्य उद्योगपति हैं। इनमें अडानी विश्व में नंबर दो पर पहुंच गए थे लेकिन चिढ़ने वालों ने उन पर ऐसे तथाकथित आरोप लगाने शुरू कर दिए जिससे उनको ज्यादा से ज्यादा तकलीफ हो, ऐसा भय फैलाया गया कि अगर वे लंदन चले जाएं, यूरोप चले जाएं, अमेरिका के प्रभाव वाले देशों में चले जाएं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो आज भारत का हर विरोधी अलग-अलग ढंग से गला घोंटना चाहता है। इसके पहले चीन पर भी ट्रम्प ने 145 प्रतिशत टैरिफ लगाया था और चीन ने भी उसका करारा जवाब दिया। आखिर हुआ क्या? ट्रम्प को झुकना पड़ा। मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूं मगर पत्रकार, राजनेता और उद्योगपति के रूप में विश्लेषण की क्षमता तो रखता ही हूं। मुझे लगता है कि अमेरिका की नजर काफी वर्षों से भारत के कृषि और डेयरी क्षेत्र पर है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान करीब 14 प्रतिशत का है और रोजगार में 42 प्रतिशत का योगदान है। डेयरी क्षेत्र का योगदान 5 प्रतिशत से कुछ ऊपर है और पशुपालन तथा उससे जुड़े उद्योगों को जोड़ लें तो साढ़े आठ प्रतिशत आबादी को रोजगार के साधन उपलब्ध कराता है। इधर दूध उत्पादन में भारत दुनिया में पहले नंबर पर है। दुनिया के दूध उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी 23 से 24 फीसदी है। दूसरे क्रम पर अमेरिका है लेकिन वहां के दूध और भारत के दूध में बहुत अंतर है। उनके यहां पशुओं को प्रोटीन आहार देने के लिए मांस का उपयोग किया जाता है जबकि भारत के दुग्ध उत्पादक पशु शाकाहारी हैं। अब देखिए कि दोनों देशों में कृषि और डेयरी क्षेत्र में अंतर क्या है? भारत में कृषि क्षेत्र को अत्यंत कम सहायता मिलती है लेकिन अमेरिका के किसानों पर अनुदान, तकनीकी सहायता और ऋण के मामले में सरकार मेहरबान है, यानी अमेरिकी कृषि क्षेत्र और वहां के किसान भारत की तुलना में अत्यंत साधन संपन्न हैं, सिर्फ अमेरिका ही नहीं, यूरोप के देश और चीन समेत कई देश कृषि पर सब्सिडी देते हैं। ऐसे में अमेरिकी कृषि और डेयरी उद्योग को भारत में अनुमति मिल गई तो हमारे किसान बाजार में नहीं टिक पाएंगे। भारतीय किसानों की आर्थिक आजादी लुट जाएगी। जहां तक हमारी आर्थिक आजादी पर चीन के हमले का सवाल है तो हम भारतीय सजग हुए हैं मगर अभी भी चीनी उत्पादों से भारतीय बाजार अटे पड़े हैं। हमारे कुटीर और लघु उद्योग भारतीय बाजार में चीन के साम्राज्य को खत्म नहीं कर पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया का जो नारा दिया उस दिशा में हम बढ़े जरूर हैं लेकिन अभी लंबी दूरी तय करना बाकी है। सरकार की दूरगामी नीति और आम आदमी की मेहनत ही स्थितियों को बदल सकती है, अभी भी हमारे यहां ब्यूरोक्रेसी का नजरिया पूरी तरह बदला नहीं है, जब तक हम लोग लेबर की प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी नहीं बढ़ाते तब तक हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर प्रतिस्पर्धी नहीं बन पाएंगे। हमें हर क्षेत्र में गुणवत्ता का ध्यान रखना ही पड़ेगा और तब हमें कोई नहीं रोक पाएगा। मैं अमेरिका की उन्नति की कहानी पढ़ रहा था तो वह प्रसंग सामने आया जब अर्थव्यवस्था चरमराने के बाद जॉन एफ. कैनेडी ने अमेरिकियों से कहा कि इस वक्त आप यह मत सोचिए कि अमेरिका मुझे क्या दे सकता है, यह सोचिए कि देश को आप क्या दे सकते हैं? उसके बाद ही अमेरिका की किस्मत बदली। भारत के संदर्भ में भी हमें इसी तरह सोचने की जरूरत है। हम खुद को हस्ती को इतना बुलंद करें कि हमलावर भी बार बार सोचे। चीन शक्तिशाली है इसलिए अमेरिका को उसको जगह बता दी। हमें पंचशील के मार्ग से भी आगे जाकर तीखे तेवर अपनाने होंगे। मुझे रामचरित मानस का एक प्रसंग याद आ रहा है। परशुराम ने जब लक्ष्मण को अपने फरसे से डराने की कोशिश की तो लक्ष्मण ने कहा- 'इहां कुम्हड़बतिया कोउ नाहीं, जो तर्जनी देखि मरि जाहीं' यानी यहां कोई भी कुम्हड़े के छोटे फल जैसा कमजोर नहीं है, जो तर्जनी उंगली दिखाने से ही मुरझा जाए। हमें याद रखना होगा कि भारत में अपार संभावनाएं हैं। पिछले दो हजार साल का आर्थिक इतिहास देखें तो शुरुआती 1500 वर्षों तक विश्व उत्पादन में भारत का योगदान औसतन 46 फीसदी था।

पाकिस्तानी गीदड़ भभकियों से नहीं डरता भारत

जब से पाकिस्तान ने चोरी-चकारी से परमाणु बम बनाया है तभी से वह भारत पर परमाणु हमला करने की धमकियां दे रहा है। पाकिस्तान के नेताओं के साथ-साथ सैन्य अधिकारी भी भारत को परमाणु हमले की धमकी देते रहे हैं। अब अमेरिका में बैठकर पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने भी भारत को परमाणु हमले की धमकी दी है। पाकिस्तान कई बार परमाणु हमले की धमकी दे चुका है, जबकि भारत ने कभी भी ऐसी धमकी किसी देश को नहीं दी है। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान में परमाणु बम का कंट्रोल है किसके पास, सरकार के पास या सेना के पास? पाक के परमाणु सिस्टम को कौन कंट्रोल करता है? क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि अगर यह बम किसी गलत हाथ में पड़ा तो विनाश तय है। यही कारण है कि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कुछ समय पूर्व अंतर्राष्ट्रीय परमाणु शक्ति संगठन से कहा था कि पाकिस्तान एक आतंकी मानसिकता का अड्डा बन चुका है और उसके आण्विक हथियार संगठन द्वारा छीन लिए जाने चाहिए, क्योंकि यह भारत ही नहीं, बल्कि पूर्ण विश्व शांति के लिए खतरा है। भारत कई बार पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर चिंता जता चुका है और दुनिया को आगाह भी कर चुका है। पाकिस्तानी सेना के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जो कि दो महीनों के अंदर दूसरी बार अमेरिका के दौरे पर हैं, क्योंकि उन्हें वहां की सेंटकॉम, अर्थात सभी प्रकार की सेनाओं के मुखिया माईकल कुरीला के विदाई कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है, वहां से वह अपनी आदत के अनुसार उल्टे-सीधे बयान जारी करते जा रहे हैं। उनके के हालिया बयान पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भारत ने कहा है कि परमाणु हमले की धमकी देना पाकिस्तान की आदत में शामिल है। विदेशी मंत्रालय का यह बयान उस रिपोर्ट के बाद आया है जिसमें आसिम मुनीर की एक चेतावनी का ज़िक्र किया गया है। अमेरिका में पाकिस्तानियों के साथ एक कार्यक्रम के दौरान आसिम मुनीर ने कहा था कि अगर भारत के साथ भविष्य की जंग में पाकिस्तान के अस्तित्व को खतरा हुआ तो वह पूरे विश्व को परमाणु युद्ध में झोंक देगा। यह एक बड़ा गैर जिम्मेदाराना है और आजकल वह पाकिस्तानी -प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग- के रोल में दिख रहे हैं। बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भी पीछे नहीं। उन्होंने भारत को सिंधु जल के ऊपर भी धमकी दे डाली कि भारत-पाक के बीच सभी नदियां पाकिस्तान जंग कर के ले लेगा। अजीब मिजाज बन गया है इन लोगों का। इसी संदर्भ में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री, इमरान खान ने कभी माना था कि भारत और पाकिस्तान बड़े और छोटे भाइयों की तरह हैं जो एक ही मां के बेटे हैं और विभाजन के समय अलग कर दिए गए। कश्मीर समस्या के बारे में उन्होंने कहा था कि इसे बैक बर्नर पर अर्थात पिछवाड़े में डाल देना चाहिए और दोनों देशों को परस्पर व्यापार, सांस्कृतिक वो खेलकूद आदि कार्यक्रमों के आदान-प्रदान पर अधिक ध्यान देना चाहिए। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा था कि बतौर एक क्रिकेट खिलाड़ी उनके संबंध भारतीय खिलाड़ियों से बड़े मधुर रहे हैं। यह अलग बात है कि आईएसआईएस के सैनिक प्रबंधन ने उन्हें भी जकड़ लिया, जिसके कारण वे भारत से दोस्ती का प्रोजेक्ट नहीं चला पाए। पाकिस्तानी सेना के प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का यह बयान भी सामने आया है जिसमें उन्होंने दावा किया है कि मई में हुए संघर्ष में पाकिस्तान को कामयाबी मिली थी। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत 'विश्व गुरु- बनने का दावा करता है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आसिम मुनीर का बयान ऐसे समय पर सामने आया है जब शनिवार और रविवार को ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय थल सेना और वायु सेना प्रमुखों के अलग-अलग बयान सामने आए थे। भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने हाल ही में आईआईटी मद्रास में एक कार्यक्रम में शिरकत की थी। जनरल द्विवेदी ने कहा था कि पहलगाम हमले के जवाब में चलाया गया 'ऑपरेशन सिंदूर' किसी भी पारंपरिक मिशन से अलग था। भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने दावा किया था कि मई में हुए संघर्ष के दौरान भारत ने 'छह पाकिस्तानी विमानों को मार गिराया था।'

हालांकि, उसी रोज पाकिस्तान के रक्षा मंत्री आसिफ ने बयान जारी कर छह विमान गिराए जाने के दावे का खंडन किया। 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हमले के बाद भारत ने बताया था कि 6-7 मई की रात भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में स्थित चरमपंथी कैंपों को निशाना बनाया है। इसके बाद दोनों देशों के बीच सैन्य संघर्ष शुरू हो गया था 10 मई को संघर्ष विराम पर सहमति बनने के बाद गोलीबारी थम गई। उस समय पाकिस्तान ने भारत के 'पांच लड़ाकू विमान गिराने' का दावा किया था, जिसे भारत ने सिरे से खारिज कर दिया था। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने अपने संबोधन में 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद नैरेटिव मैनेजमेंट पर भी अपनी बात रखी। जनरल द्विवेदी ने कहा, 'नैरेटिव मैनेजमेंट सिस्टम वह चीज़ है जिसे हमने बड़े पैमाने पर समझा, क्योंकि जीत दिमाग में होती है, हमेशा दिमाग में रहती है अगर आप किसी पाकिस्तानी से पूछें कि आप हारे या जीते, तो वह कहेगा- 'मेरा चीफ फ़ील्ड मार्शल बन गया है। हम जीते हैं, तभी वह फ़ील्ड मार्शल बना है'।' दरअसल, यह टिप्पणी उन्होंने पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर के फ़ील्ड मार्शल बनने के संदर्भ में की, जिन्हें भारत-पाकिस्तान संघर्ष के कुछ ही दिनों बाद पाकिस्तान सरकार ने यह पद दिया था।

ग़लत बात, आप हमारे डाके को 'वोट चोरी' कहते हैं!

रात का समय था। सारा संसार सो गया था। पर सरकार जी की आँखों से नींद जैसे कोसों दूर थी। उम्र सत्तर पार हो चुकी थी। समझो पिचहत्तर पहुँचने ही वाली थी। वैसे भी इस उम्र में नींद कम ही आती है पर आज नींद कम आने का कारण ही कुछ और था। उन्हें चोर कह दिया गया था। नहीं, नहीं, उन्हें यह चिंता नहीं थी कि उन्हें चोर क्यों कहा गया। उन्हें वोट चोर कहा गया था। उनकी चिंता यह थी कि हम डाका डालें और तुम हमें सिर्फ चोर कहो। यह बात तो ठीक नहीं है। एक डाकू को अगर चोर कहा जायेगा तो उसे चिंता तो होगी ही। कारनामों को डाउनग्रेड करने से किसी को भी चिंता तो होगी ही। सरकार जी ने यह कारनामा केंचुआ के साथ मिल कर किया है। ध्यान रहे यह केंचुआ वह केंचुआ नहीं है जिसकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती है और जो जमीन पर रेंग रेंग कर चलता है। वैसे कुछ लोग यह भी मानते हैं कि इस केंचुआ और उस केंचुए में अब कोई फर्क नहीं बचा है। पर इस केंचुआ में आदमी होते हैं जो भले ही चरित्र में उस केंचुआ जैसे ही होते हों पर होते आदमी ही हैं। तो हमारे यहाँ इसी केंचुआ की कृपा से, जब सब कुछ नकली बन सकता है, हर तरह का सर्टिफिकेट नकली बन सकता है। किसी की डिग्री तक नकली बन सकती है तो वोट तो नकली बन ही सकते हैं, और बन भी रहे हैं। हमारे देश में एक कमरे के घर में अस्सी लोगों के वोट बन रहे हैं। मतलब वन बीएचके फ्लैट के पते पर अस्सी वोटर आईडी कार्ड इशु हो रहे हैं। और केंचुआ की कृपा से ही इशु हो रहे हैं। और इस पर नेता प्रतिपक्ष को संदेह है कि एक कमरे में अस्सी लोग कैसे रह रहे होंगे। क्यों भई, संदेह क्यों है। सुना है, मुंबई में कुछ ऐसे कमरे किराये पर मिलते हैं जहाँ तीन-चार बिस्तर पड़े होते हैं और हर शिफ्ट में तीन चार किरायेदार रहते हैं। आठ घंटे के लिए सोने के लिए आते हैं और फिर आठ घंटे बाद दूसरे लोगों की सोने की शिफ्ट शुरू हो जाती है। वे लोग सोने आ जाते हैं। पर यह एक कमरे के मकान में अस्सी वोट की बात मुंबई में नहीं, बेंगलूरु में हुई है। हो सकता है, वहाँ, बेंगलूरु में लोग एक एक घंटे की शिफ्ट में किरायेदार बनते हों, सोने आते हों और उठ कर चले जाते हों। फिर दूसरे लोग एक घंटे की शिफ्ट में सोने आ जाते हों। आई टी हब है, इतनी उन्नति तो हुई ही होगी। तो हो गए ना अस्सी लोग एक कमरे में। एक कमरे में पांच बिस्तर लगे हों तो एक सौ बीस तक वोटर हो सकते हैं। इसी तरह से छोटे छोटे शहरों में भी एक एक मकान में दो सौ, तीन सौ वोटर तक बने हुए हैं। यह आरोप भी लगाया गया कि बहुत सारे वोट मकान नंबर जीरो, मतलब मकान नंबर शून्य के भी बने हुए हैं। यह भविष्य की बात है, नेता प्रतिपक्ष को समझ नहीं आएगी। नेता प्रतिपक्ष, मैं आपको समझाता हूँ। शून्य का अविष्कार किसने किया? हमने ना। तो फिर हम मकानों के नंबर किसी और संख्या से क्यों रखें। अब केंचुआ अगर यह प्रयोग कर रहा है कि मकानों के नंबर शून्य ही हों तो आपको क्या दिक्कत है। अभी कुछ मकानों के लिए यह प्रयोग किया है, फिर अधिकतर के मकानों के नंबर शून्य होंगे और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि सभी मकानों के नंबर शून्य, मतलब जीरो होंगे।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा आवारा कुत्तों पर स्वतःसंज्ञान के 14 दिनों में सुप्रीम न्याय की ऐतिहासिक गूँज- कबूतरों को दाना खिलाने पर भी सुप्रीम निर्णय

वैश्विक स्तरपर भारतीय न्यायपालिका की प्रतिष्ठा पारदर्शिता व निष्पक्षता का गुणगान यूं ही नहीं किया जाता, यहां मानवीय संवेदनशीलता के साथ- साथ-साथ मूक बधिर जीवों की सुरक्षा करने के साथ साथ संवेदनशीलता, व उनको हिंसा से मानवीय जीवों को बचाने उनकी सुरक्षा करने के लिए स्वतः संज्ञान भी लिया जाता है।मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं कि भारत माता की मिट्टी में पैदा हुए हर व्यक्ति में सृष्टि में पैदा हुए जीवों के प्रति गहरी संवेदनाओं संवेदनशीलता गुण हृदय में भरा रहता है जो किसी न किसी रूप में झलक जाता है, ऐसा ही हमने देखे कि आवारा कुत्तों के संबंध में स्वयंसेवी संगठन व माननीय न्यायालय तथा कबूतरों के संबंध में एक संगठन व माननीय न्यायालय के केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिनांक 11 अगस्त 2025 को अहम् फैसला दिया है।एक बच्ची को आवारा कुत्तों द्वारा काटने पर उसकी मृत्यु हो गई इसके स्वतः संज्ञान पर बेंच ने लावारिस कुत्तों की समस्या से जूझ रहे दिल्ली को लेकर बड़ा आदेश दिया है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा है कि 8 सप्ताह के भीतर सभी लावारिस कुत्तों को पकड़कर डॉग शेल्टर में शिफ्ट किया जाए व इन कुत्तों को वापस नहीं छोड़ा जाएगा। दिल्ली में रोहिणी के पास पूठ कलां में आवारा कुत्ते के काटने से रेबीज के कारण 6 साल की बच्ची की मौत के बाद 28 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने इस समस्या का स्वतःसंज्ञान लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर प्रकाशित एक मीडिया रिपोर्ट का जिक्र करते हुए इसे 'बेहद परेशान करने वाला और चिंताजनक बताया था। अदालत ने कहा था कि शहर और उसके बाहरी इलाकों में हर दिन सैकड़ों कुत्तों के काटने की खबरें आ रही हैं। कुत्तों के काटने से रेबीज हो रहा है।आमतौर पर बच्चे और बुजुर्ग इसके शिकार हो रहे हैं।सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, एमसीडी और एनडीएमसी को निर्देश दिया है कि वे तत्काल प्रभाव से आवारा कुत्तों को सभी इलाकों से पकड़ना शुरू करें,कोर्ट ने कहा कि यह कदम बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी है, जिससे वे बिना किसी डर के पार्कों और सड़कों पर जा सकें,कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि पकड़े गए कुत्तों को किसी भी परिस्थिति में वापस उन्हीं इलाकों में नहीं छोड़ा जाएगा ,इस आदेश का मकसद राष्ट्रीय राजधानी को आवारा कुत्तों से मुक्त करना है।सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार, एमसीडी और एनडीएमसी को 8 हफ्तों के अंदर करीब 5000 कुत्तों के लिए शेल्टर होम बनाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि इन शेल्टर्स में कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण के लिए पर्याप्त कर्मचारी होने चाहिए। कोर्ट ने अधिकारियों को इस बुनियादी ढांचे को तैयार करने और नियमित अंतराल पर इसकी संख्या बढ़ाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि यह कार्रवाई इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक शेल्टर बनते हैं, तब तक और लोग कुत्तों के काटने का शिकार हो सकते हैं। दूसरी ओर 11 अगस्त 2025 को ही मुंबई में कबूतरों को दाना खिलाने पर लगे प्रतिबंध के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है और याचिकाकर्ताओं से हाईकोर्ट जाने को कहा है। इतना ही नहीं माननीय पीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ भीड़ द्वारा दादर कबूतरखाना को जबरदस्ती खोलने और कबूतरों को दाना डालने की घटना पर गुस्सा जाहिर करते हुए कहा है कि जो लोग भी, इस तरह कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं, इन्हें गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाए।इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे,सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान लेने के 14 दिनों के भीतर निर्णय की फास्ट ट्रैक प्रवृत्ति जनहित की आपात समस्या निदान का सटीक उदाहरण सराहनीय है। साथियों बात अगर हम सुप्रीम कोर्ट द्वारा आवारा कुत्तों संबंधित स्वतः संज्ञान पर एक बेंच द्वारा दिए गए जजमेंट की करें तो, यह संज्ञान 28 जुलाई 2025 को लिया था। उस दिन कोर्ट ने टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित -सिटी होउंडेड बाय स्ट्रास, किड्स पे प्राइस - शीर्षक वाले समाचार लेख को आधार मानकर मामला अपने संज्ञान में लिया और इसे -सु मोटो रिट पेटिशन (सिविल) नो. 5/2025- 'सिटी होउंडेड बाय स्ट्रास, किड्स पे प्राइस-के रूप में रजिस्टर्ड किया था। कोर्ट ने दिल्ली सरकार व नगर निकायों (एमसीडी) को 11 अगस्त 2025 तक जवाब दाखिल करने का निर्देश भी जारी किया था। जिसकी मुख्य बातें इस प्रकार है।(1) तत्काल कारवाई का आदेशसुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया किदिल्ली-एनसीआर (दिल्ली-एनसीआर) सहित नोएडा,गुरुग्राम,और गाजियाबाद के सभी स्थानीय निकायों को आवारा कुत्तों को तुरंत पकड़कर शेल्टर में ले जाने की प्रक्रिया तुरंत प्रारंभ करनी चाहिए, चाहे वे नसबंद (स्टेरिलाइज्ड) हों या नहीं। कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया कि "एक भी कुत्ता सार्वजनिक स्थानों पर वापस नहीं छोड़ा जाएगा।"(2)शेल्टर्स व संरचना की व्यवस्था-कोर्ट ने दिल्ली सरकार,एमसीडी औरएनडीएमसी को निर्देशित किया कि वे आने वाले आठ सप्ताह के भीतर पर्याप्त कुत्ते शेल्टर तैयार करें, जहां नसबंदी,टीकाकरण, रखरखाव,और संरक्षित परिवेश सुनिश्चित किया जा सके। इन शेल्टरों में पिछले निर्णयों के विपरीत, सीसीटीवी लगाए जाएंगे और पर्याप्त कर्मचारी लगाए जाएंगे जिससे कोई कुत्ता बच न जाए। (3) अवरोध करने वालों के खिलाफ कार्रवाई-कोर्ट ने सख्त चेतावनी दी कि अगर कोई व्यक्ति या संगठन इस कार्य में बाधा डालता है-जैसे किशेल्टर स्थापित करने या कुत्ते पकड़ने में-तो उसके खिलाफ न्यायिक कार्रवाई (कानूनी कदम) की जाएगी। यह स्पष्ट किया गया कि यह आदेश सार्वजनिक हित (लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट) में है, और-इनफाट्स एंड यंग चिल्ड्रन, नॉट एट एनी कॉस्ट, शुड फॉल प्रे टू रेबीज-यह संदेश पूरी सख्ती के साथ दिया गया। (4) हेल्पलाइन और टीकाकरण व्यवस्था-कोर्ट ने आदेश दिया कि एक डॉग-बाइट हेल्पलाइन एक सप्ताह के भीतर स्थापित की जाए, जिस पर लोग कुत्ते काटने की घटनाओं की सूचना दे सकें। इसके साथ ही, राज्य सरकार को टीकों की उपलब्धता, स्टॉक, और इससे संबंधित जानकारी नियमित रूप से उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। (5) एबीसी रूल्स का विरोध-सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आक्षेप जताया कि एनिमल बर्थ कंट्रोल (एबीसी) नियम, जो नसबंद और टीकाकृत कुत्तों को उनके पहले स्थान पर वापिस छोड़ने की परंपरा स्पष्ट रूप से -अब्सर्ड-और- अनरेसनेबल- है।अदालत ने कहा,-फॉरगेट द रूल्स एंड फेस रियलिटी-, यह कहते हुए कि **समाज को आवारा कुत्तों से मुक्त होना चाहिए,चाहे वे नसबंद हों या नहीं।* (6) लोकहित की प्राथमिकता- कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया जिसमें लोकहित (पब्लिक इंटरेस्ट) को सर्वोच्चता दी गई। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से एनीमल राइट्स पर आधारित संगठनात्मक हस्तक्षेप को अस्वीकार कर दिया और कहा कि इस विषय में केवल विशेषज्ञ सलाह (अमिकस कुरिए) और सरकारी पक्ष की सुनवाई की जाएगी-नॉट एनिमल एक्टिविस्ट्स ओर अदर पेटिशनर्स। (7) कानूनी स्थिति-आदेश स्पष्ट रूप से बताता है कि यह मामला एक सु मोटो रिट पेटिशन है, जिसका विषय बच्चों और बुजुर्गों पर आवारा कुत्तों का जानलेवा खतरा है, और टाइम्स ऑफ इंडिया की समाचार रिपोर्ट को आधार बनाकर अदालत ने इस मामले में हस्तक्षेप किया। यह निर्णय न्यायिक उत्सर्जन (जुडीशल इंटरवेंशन) का एक उदाहरण है, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने समस्या की गम्भीरता को देखते हुए सक्रिय भूमिका निभाई। साथियों बात अगर हम 11 अगस्त 2025 को ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा कबूतरों को दान देने संबंधी जजमेंट की करें तो,सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया जिसमें कहा गया था कि कबूतरों को खाना खिलाने से गंभीर स्वास्थ्य संबंधी खतरे पैदा होते हैं। साथ ही, कोर्ट ने बृहन्मुंबई नगर निगम को उन लोगों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने का निर्देश दिया जो निगम के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए मुंबई के कबूतरखानों में कबूतरों को खाना खिलाना जारी रखते हैं।

माननीय दो जजों की पीठ ने कहा,-इस न्यायालय द्वारा समानांतर हस्तक्षेप उचित नहीं है। याचिकाकर्ता आदेश में संशोधन के लिए हाईकोर्ट जा सकता है।पीठ ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ भीड़ द्वारा दादर कबूतरखाना को जबरदस्ती खोलने और कबूतरों को दाना डालने की घटना पर गुस्सा जाहिर करते हुए कहा है कि जो लोग भी, इस तरह कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं, इन्हें गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाए।

अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा आवारा कुत्तों पर स्वतःसंज्ञान के 14 दिनों में सुप्रीम न्याय की ऐतिहासिक गूंज-कबूतरों को दाना खिलाने पर भी सुप्रीम निर्णय,सुप्रीम कोर्ट का संवेदनशील हस्तक्षेप- आवारा कुत्तों से सुरक्षा व कबूतरों पर अहम् जजमेंट,सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वतःसंज्ञान लेने के 14 दिनों में निर्णय की फास्ट ट्रैक प्रवृत्ति जनहित की आपात समस्या निदान का सटीक उदाहरण सराहनीय।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार भाटी ने वन्दना ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, साउथ पैंसलखेल एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार भाटी, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2011/00882)

14 अगस्त को भाजपा मनाएगी विभाजन विभीषिका दिवस

पडरौना, कुशीनगर।

देश का विभाजन कैसे हमारे लिए विभीषिका बनी, इसे याद करने और भारत की वर्तमान और भावी पीढ़ियों को विभाजन के दौरान लोगों द्वारा सही गई यातना और वेदना का स्मरण दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2021 में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में घोषित किया था। भारतीय जनता पार्टी द्वारा हर वर्ष देश बंटवारे के दर्द को याद करते हुए विभाजन विभिषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है। इस बार भी 14 अगस्त को भाजपा द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उक्त जानकारी जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय के हवाले से जिला मीडिया प्रभारी विश्वरंजन कुमार आनन्द ने दी। मीडिया प्रभारी ने बताया कि विभाजन विभिषिका दिवस पर गुरुवार दिनांक 14 अगस्त को सुबह 11:00 बजे रविन्द्र नगर भाजपा कार्यालय में विभाजन विभिषिका दिवस पर संगोष्ठी दोपहर 1:00 बजे रविन्द्र नगर भाजपा कार्यालय से चन्द्रशेखर आजाद चौक तक मौन जुलूस और अपराह्न 02 बजे हनुमान इण्टर कालेज पडरौना में प्रदर्शनी लगाई जाएगी। सभी कार्यक्रमों में बतौर मुख्य अतिथि किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर सिंह होंगे। जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय ने सांसद, विधायक जिला पंचायत अध्यक्ष, पूर्व जिलाध्यक्ष,पूर्व विधायक, ब्लाक प्रमुख, प्रतिनिधि नगर पालिका व नगर पंचायत अध्यक्ष,भाजपा जिला पदाधिकारी, विभाग प्रकोष्ठ तथा मोर्चो के जिला पदाधिकारी,मण्डल प्रभारी, मण्डल अध्यक्ष,तिरंगा अभियान के जिला संयोजक सह संयोजक,वरिष्ठ नेता एवं आई टी तथा सोशल मीडिया जिला संयोजक व सह संयोजक से सभी कार्यक्रमों में उपस्थित रहने का आग्रह किया है।

नगर पालिका अध्यक्ष ने छात्र-छात्राओं से किया संवाद

हर घर तिरंगा अभियान में सभी को अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का किया आह्वान

पडरौना कुशीनगर।

नगर पालिका परिषद् पडरौना कार्यालय के प्रथम तल पर स्थित ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ जी पुस्तकालय में आज का दिन विशेष उत्साह और देशभक्ति की भावना से परिपूर्ण रहा।

पुस्तकालय में अध्ययनरत प्यारे बच्चों और बच्चियों को हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय ध्वज वितरित किए गए। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष विनय जायसवाल ने बच्चों के साथ आत्मीय संवाद करते हुए तिरंगे के महत्व, उसके तीन रंगों के प्रतीकात्मक अर्थ तथा हमारे स्वतंत्रता संग्राम में इसकी गौरवपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। श्री जायसवाल ने बच्चों को यह भी प्रेरित किया कि वे अपने परिवार, पड़ोस और मित्रों को हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ने के लिए प्रेरित करें, ताकि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सम्पूर्ण नगर तिरंगे की रोशनी में जगमगाए। कार्यक्रम के दौरान पुस्तकालय का वातावरण देशभक्ति के गीतों, बच्चों की हँसी-खुशी और उत्साह से गूंज उठा। बच्चों ने तिरंगा हाथ में लेकर भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए। इस दौरान कई बच्चों ने तिरंगे के साथ फोटो खिंचवाए, जो इस यादगार पल को हमेशा के लिए संजोने वाला क्षण बना। इस दौरान पुस्तकालय संचालक निशा गुप्ता, सहित छात्र छात्राओं अनामिका, संजना मिश्रा, नेहा जायसवाल, दिशा जायसवाल, अर्चना विश्वकर्मा, अक्षय वर्मा, अनुराग चंद्र, नीतीश शुक्ला, दीपक खरवार, राहुल भारती सहित सभी ने मिलकर इस पहल की सराहना की और इसे राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने वाला कदम बताया।

विधिक सेवा प्राधिकरण की मध्यस्थता से सुलह, दंपति ने फिर थामा एक-दूजे का हाथ

देवरिया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि संवेदनशील मध्यस्थता, टूटते रिश्तों में भी नई शुरुआत की संभावना जगा सकती है। बुधवार को सचिव/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी के नेतृत्व में हुई मध्यस्थता के जरिए ग्राम मदनचक, थाना भाटपार रानी के दंपति रेखा और सुनील के बीच लंबे समय से चला आ रहा वैवाहिक मनमुटाव खत्म हो गया। प्रकरण की शुरुआत तब हुई जब विवाह के बाद उत्पन्न मतभेदों ने पति-पत्नी को अलग-अलग रहने पर मजबूर कर दिया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के विधिक जागरूकता एवं साक्षरता कार्यक्रम से प्रेरित होकर मामला प्राधिकरण के समक्ष पहुंचा। सचिव मनोज कुमार तिवारी और मध्यस्थ अनिल कुमार सिंह ने दोनों पक्षों को आमने-सामने बैठाकर न केवल संवाद कराया, बल्कि उन्हें वैवाहिक जीवन के वचनों और पारिवारिक जिम्मेदारियों का बोध भी कराया।

देशभक्ति के जज्बा,जोश और उत्साह के साथ निकली तिरंगा यात्रा

पडरौना, कुशीनगर।

भारतीय जनता पार्टी द्वारा बुधवार को 9 मण्डलों में पूरे जोश, उत्साह और उमंग के साथ भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी व जनप्रतिनिधियों ने हाथ में तिरंगा लेकर 'भारत मां की जयकार, वंदे मातरम' की गूंज के साथ यात्रा का नेतृत्व किया। देशभक्ति के रस में सराबोर हजारों लोग तिरंगा यात्रा में सहभागी बने। भाजपा जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय फाजिलनगर विधानसभा के तुर्क पट्टी मण्डल में मण्डल अध्यक्ष महेन्द्र शर्मा के साथ तिरंगा यात्रा का नेतृत्व किया। जिलाध्यक्ष ने बताया कि हर घर तिरंगा अभियान के अन्तर्गत विगत तीन दिन में भारतीय जनता पार्टी द्वारा जनपद के सभी 34 मण्डलों सहित सैकड़ों शक्ति केंद्रों में भव्य और ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा निकाली गई जिसमें लाखों लोग सहभागी बने और बलिदानियों को नमन किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि तिरंगा हमारे दिलों में है, हमारे कार्यों में है और यह हमारा गौरव है।

यह हमारे पूर्वजों के त्याग और देशभक्ति की अमूल्य विरासत है। यह यात्रा लोगों को एकजुट कर देश की एकता और अखंडता को मजबूती प्रदान करती है। जिला मीडिया प्रभारी विश्वरंजन कुमार आनन्द ने बताया कि कुशीनगर विधानसभा के टेकुआटार मण्डल में पूर्व जिलाध्यक्ष जगदम्बा सिंह, पूर्व विधायक रजनीकांत मणि त्रिपाठी व मण्डल अध्यक्ष राजेश राव के नेतृत्व भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई।

इसी तरह खड्डा विधानसभा के खड्डा मण्डल में जिला उपाध्यक्ष मनोज जायसवाल नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि दुर्गेश्वर वर्मा,भुजौली मण्डल में पूर्व विधायक मदन गोविंद राव व मण्डल अध्यक्ष दिग्विजय शर्मा, नौरंगिया मण्डल में किसान मोर्चा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हरिशंकर राय, ब्लाक प्रमुख प्रतिनिधि शेषनाथ यादव व मण्डल अध्यक्ष सूरज गोविंद राव तथा बगहीधाम मण्डल में पूर्व चेयरमैन डॉ निलेश मिश्र, मण्डल अध्यक्ष सर्वजीत गुप्ता तथा पूर्व मण्डल अध्यक्ष हरि गोविंद रौनियार के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई।

इसी तरह हाटा विधानसभा के अहिरौली मण्डल में जिला मंत्री बाबू नन्दन सिंह, ब्लाक प्रमुख प्रतिनिधि संदीप सिंह व मण्डल अध्यक्ष मनोज पाण्डेय और रामकोला विधानसभा के मथौली मण्डल में जिला महामंत्री राणा प्रताप राव, नगर पंचायत अध्यक्ष नवरंग सिंह व मण्डल अध्यक्ष अदालत प्रसाद आर्या के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई।

तिरंगे की शान में निकली रैली, गाँव- गाँव गूँजा देशभक्ति का स्वर

भटनी देवरिया।

दिन बुधवार को राम गुलाम राय पी.जी. कॉलेज, बनकटा शिव सल्लहपुर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत भव्य रैली का आयोजन किया गया। रैली को महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. राजेश्वर शाही ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया। रैली ग्राम सभा बनकटा शिव सल्लहपुर के सभी टोलों से होकर गुजरी, जहां लोगों को हर घर तिरंगा अभियान के महत्व और राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के प्रति जागरूक किया गया। इस अवसर पर डॉ. अनिल कुमार सिंह, डॉ. कमलेश मिश्र, डॉ. राधारमण मिश्र, डॉ. संदीप कुमार सोनकर, डॉ. मनमोहन सिंह, डॉ. राहुल मिश्र, डॉ. कविता मिश्रा, डॉ. अब्दुल हमीद, डॉ. चंद्रशेखर तिपाठी, अंजली तिवारी, निशु मिश्र समेत समस्त छात्र-छात्राओं की सक्रिय भागीदारी रही।

खड्डा में बारिश से सड़कें कीचड़ और पानी से भरी

12 गांवों का संपर्क मार्ग टूटने के कगार पर, आवागमन प्रभावित

नेबुआ नौरंगिया, कुशीनगर । कुशीनगर और महराजगंज जनपद के नदी पार बसे दर्जनों गांवों के लिए आने-जाने का एकमात्र साधन बस है, लेकिन मौजूदा बरसात के मौसम में यह सेवा भी खतरे में है।लगातार बारिश के चलते सड़कें कीचड़ और पानी से भर गई हैं, जिससे बसों का संचालन मुश्किल हो गयाहै। यदि यही स्थिति रही, तो आने वाले दिनों में इन गांवोंका जिला मुख्यालय से संपर्क पूरी तरह टूट सकता है। कुशीनगर के नारायणपुर, हरिहरपुर, मारचहवा, शिवपुरतथा महराजगंज के सोहागी बरवा और भोथहा जैसे गांवों के लोग रोज मार्ग की यात्रा के लिए केवल बस पर निर्भर हैं। कुशीनगर मुख्यालय पहुंचने के लिए ग्रामीणों को रोहुआ नाला पार करना पड़ता है। इस नाले पर ह्यूमन पाइप तो लगाया गया है, लेकिन पोर्च(सुरक्षात्मक ढांचा) का निर्माण आज तक नहीं हुआ। पिछले महीने महराजगंज के जिलाधिकारी ने इस मार्गका निरीक्षण किया था। उस समय पाइप पर अस्थायी तौर पर मिट्टी डाली गई थी, ताकि आवागमन सुचारू रह सके। लेकिन बरसात के कारण मिट्टी बह गई औरस्थिति पहले जैसी हो गई। अब भी लोगों को बगल के गड्ढे में जमा पानी से होकर ही गुजरना पड़ता है।ग्रामीणों का कहना है के हर साल बारिश के बाद इस जगह नाव चलने लगती है और सड़क संपर्क बाधित हो जाता है। मौजूदा हालात में बस सेवाएं भी कुछ ही दिनोंमें बंद हो सकती हैं, जिससे न केवल आवागमन रुकेगा,बल्कि आपात स्थिति में स्वास्थ, शिक्षा और जसरूरी सेवाओं तक पहुंचना भी असंभव हो जाएगा।इसके अलावा, इन गांवों में सड़क और पुलिया निम्माणकी स्थिति बेहद खराब है। वर्षों से सड़क बनाने या पुलिया निर्माण के लिए मांग की जा रही है, लेकिन अबतक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। रात में प्रकाश व्यवस्था के अभाव से स्थिति और भी खतरनाक हो जाती है। भारी बारिश होने के बाद नदी में नाव भी नहीं चलती है जिसके कारण नदी का भी रास्ता बाधित हो जाता है बस के अलावा नाव भी एक मुख्यालय जोड़ने का साधन है जो बाढ़ में संभव नहीं है।

आपको जो हुनर आए उसी को बनाएं कमाई का जरिया

देवरिया।

एक सफल कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए कोर्स करना जरूरी नहीं है। हर व्यक्ति में कोई न कोई ऐसा कौशल होता है, जिसका सही इस्तेमाल करके आप सोशल मीडिया के माध्यम से पैसे कमा सकते हैं। यह बातें देश के चर्चित यूट्यूबर और कंटेंट क्रिएटर सतीश कुशवाहा ने जागृति उद्यम केंद्र-पूर्वांचल के बरपार स्थित बरगद सभागार में आयोजित कंटेंट क्रिएटर्स कार्यशाला में कहीं। मंगलवार को आयोजित इस कार्यशाला में देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर और आसपास के जिलों के क्रिएटर्स ने हिस्सा लिया। सतीश कुशवाहा ने कहा कि कंटेंट क्रिएशन में असीमित संभावनाएं हैं, जिसमें लोग महीने का लाखों रुपये कमा रहे है और उन्हें बड़े-बड़े स्पॉन्सर आसानी से मिल रहे हैं। अगर आप कार मैकेनिक हैं, तो भी अपने काम के बारे में वीडियो बनाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नियमित डालना शुरू करें, पैसे आने लगेंगे। उन्होंने बताया कि कई महिलाएं शादी के गीत रिकॉर्ड करके यूट्यूब व अन्य सोशल साइट्स पर अपलोड करती हैं और उनके लाखों फॉलोअर्स हैं। छात्र अपनी पढ़ाई का वीडियो भी बना सकते हैं। उन्होंने

जागृति उद्यम केंद्र के बरगद सभागार में आयोजित हुई कंटेंट क्रिएटर कार्यशाला

देश के चर्चित कंटेंट क्रिएटर सतीश कुशवाहा ने इंफ्लुएंसर्स को वीडियो से पैसे कमाने के सिखाए नुस्खे

कहा कि व्यूवर कम मिलने या फॉलोअर्स न बढ़ने से हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। आप अपने काम की समीक्षा दूसरों से कराते रहें। जो कमी पता चले, उसमें सुधार करते रहें, सफलता का रास्ता अपने आप मिल जाएगा। वीडियो बनाते समय खुद से तीन सवाल जरूर करें- क्या दिखाना चाहते हैं? किसको दिखाना चाहते हैं? और क्यों दिखाना चाहते हैं? जब इन सवालों के जवाब संतोषजनक मिलें, तो समझ लीजिए कि वीडियो पर व्यूज मिलना और फॉलोअर्स बढ़ना स्वाभाविक है। वीडियो बनाते समय लाइट, कैमरा और ऑडियो पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर इनमें से किसी एक में भी तालमेल बिगड़ गया, तो अपनी कला को दर्शकों तक सही तरीके से नहीं पहुंचा पाएंगे। कार्यशाला में सतीश कुशवाहा ने यूट्यूब पर चैनल, थंबनेल बनाने, सब्सक्राइबर बढ़ाने, चैनल को मॉनिटाइज करने की बारीकियां बताईं। जागृति के प्रोग्राम मैनेजर मनीष बजाज ने बताया कि सतीश मूल रूप से देवरिया जिले के रहने वाले है और यूट्यूब पर इनके दो मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स हैं। उन्होंने कहा, आपके भीतर भी वह प्रतिभा है, जिसे जागृत करने के लिए जागृति की ओर से इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है। असिस्टेंट प्रोग्राम मैनेजर अनुराग तिवारी ने कहा कि कंटेंट क्रिएशन एक ऐसा कार्य है, जिसे आप पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। इस दौरान कंटेंट राइटर बैकुंठनाथ शुक्ल, उद्यम कोर अभिषेक सिंह एडमिन विकास शाही, दिव्या पांडेय, संज्ञा यादव आदि मौजूद रहे।

एनजीओ के भरोसे है लावारिस कुत्तों को पकड़कर नसबंदी कराने का काम, एमसीडी ने शुरू की जगह की तलाश

नई दिल्ली। राजधानी में लावारिस कुत्तों को पकड़ने की पूरी जिम्मेदारी फिलहाल गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के कंधों पर है। एमसीडी इनके माध्यम से कुत्तों की नसबंदी करवाता है और उन्हें पकड़ने में इनकी मदद लेता है। एमसीडी के पास खुद वाहन और कर्मचारी हैं, लेकिन संख्या बेहद कम होने के कारण बड़ी संख्या में शिकायतें आने पर उसको एनजीओ पर ही निर्भर रहना पड़ता है। एमसीडी ने कुत्तों की नसबंदी के लिए 20 केंद्र बना रखे हैं, जिनमें से फिलहाल 13 केंद्रों पर काम चल रहा है। यह सभी केंद्र एनजीओ की देखरेख में संचालित हो रहे हैं। एमसीडी अधिकारियों के मुताबिक तीनों नगर निगम के एकीकरण के बाद वर्ष 2022-23 में 60 हजार कुत्तों की नसबंदी की गई थी। उसके बाद वर्ष 2023-24 में यह आंकड़ा 80 हजार तक पहुंचा, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1.30 लाख कुत्तों की नसबंदी की गई। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में एक अप्रैल से 31 जुलाई तक ही 40 हजार कुत्तों की नसबंदी हो चुकी है। आंकड़ों के मुताबिक, पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान प्रतिमाह लगभग 10 हजार कुत्तों को पकड़कर उनकी नसबंदी की जा रही है। वर्तमान नियमों के तहत नसबंदी के बाद कुत्तों को उसी इलाके में छोड़ दिया जाता है, जहां से उन्हें पकड़ा गया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के सोमवार को आए आदेश ने स्थिति बदल दी है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि कुत्तों को पकड़ कर शेल्टर में रखा जाए। इस आदेश को लागू करने के लिए एमसीडी को बड़े पैमाने पर संसाधन जुटाने होंगे। इसका मतलब है कि अब न सिर्फ कुत्तों को पकड़ना और नसबंदी करना होगा, बल्कि उनके लिए स्थायी या दीर्घकालिक आश्रय स्थलों की भी व्यवस्था करनी होगी। अधिकारियों का कहना है कि मौजूदा ढांचे और संसाधनों के आधार पर यदि सिर्फ एनजीओ पर निर्भर रहा जाए तो सभी कुत्तों को पकड़ने और नसबंदी करने में कई साल लग जाएंगे। इस कारण उसको अपनी टीम बढ़ानी होगी, वाहन बढ़ाने होंगे और नसबंदी केंद्रों की क्षमता में विस्तार करना होगा। एमसीडी के सामने अब दोहरी चुनौती है। पहली, तेजी से नसबंदी अभियान चलाकर कुत्तों की संख्या पर नियंत्रण पाना और दूसरी, कोर्ट के आदेश के तहत उनके लिए पर्याप्त आश्रय स्थलों की व्यवस्था करना।

सुप्रीम कोर्ट के सोमवार को आए आदेश के मद्देनजर एमसीडी ने लावारिस कुत्तों को पकड़कर सुरक्षित रखने के लिए काम शुरू कर दिया है। पशु विभाग फिलहाल ऐसे स्थानों की तलाश में जुटा है जो खाली हो और अगले कुछ वर्षों तक अन्य किसी काम में उपयोग होने की संभावना नहीं है। इन स्थानों को अस्थायी रूप से कुत्तों को रखने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। एमसीडी के सूत्रों के अनुसार, राज्य सरकार से भी ऐसे स्थल उपलब्ध कराने पर बातचीत शुरू की गई है, जहां बड़ी संख्या में पकड़े गए कुत्तों को अस्थायी रूप से रखा जा सके। बताया जा रहा है कि कुत्तों को पकड़ने का अभियान आने वाले दिनों में मौजूदा गति से कहीं अधिक तेज होगा। सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी को आठ सप्ताह में 5,000 कुत्ते पकड़ने का लक्ष्य दिया है, जिसे पूरा करने के लिए एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार की गई है।

स्वतंत्रता दिवस समारोह को देखते हुए फिलहाल एमसीडी की सभी टीमें लाल किले और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रित हैं। केंद्र सरकार ने सुरक्षा कारणों से इस क्षेत्र से कुत्तों को तुरंत हटाने के निर्देश दिए हैं।

कांग्रेस ने 'वोट चोरी' पर वीडियो जारी किया, चुनाव आयोग को 'इलेक्शन चोरी आयोग' बताया

नई दिल्ली।

कांग्रेस ने मतदाता सूचियों में कथित 'धांधली' के खिलाफ अपने अभियान को तेज करते हुए बुधवार को एक वीडियो जारी कर लोगों से इससे जुड़ने की अपील की और चुनाव आयोग को 'इलेक्शन चोरी आयोग' करार दिया। मुख्य विपक्षी दल ने अपने विभिन्न सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से जो एक मिनट का वीडियो जारी है उसमें दिखाया गया कि दो लोग एक मतदान केंद्र से बाहर निकलते हैं और वहां पहुंचे एक बुजुर्ग पुरुष और एक महिला से कहते हैं वे वापस चले जाएं क्योंकि वो उनका वोट पहले ही डाल चुके हैं। इस वीडियो में चुनाव आयोग के लिए 'इलेक्शन चोरी' आयोग लिखा गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने एक वीडियो साझा करते हुए 'एक्स' पर पोस्ट किया, ''मत छीनने दीजिए अपना वोट का अधिकार, सवाल कीजिए, जवाब मांगिए, इस बार। 'वोट चोरी' के खिलाफ आवाज उठाइए, संवैधानिक संस्थानों को भाजपा के चंगुल से छुड़ाइए।'' पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने भी यह वीडियो साझा कर लोगों से कांग्रेस के अभियान के साथ जुड़ने की अपील की। पिछले बृहस्पतिवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के आंकड़ों का हवाला देते हुए दावा किया था कि कर्नाटक में बेंगलुरु मध्य लोकसभा सीट के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में एक लाख से अधिक मतों की 'चोरी' की गई, जबकि इस संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस उम्मीदवार को 32 हजार वोटों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा। चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता के दावे को आधारहीन बताया था और कहा था कि वह या तो शपथ पत्र दें या फिर माफी मांगें।

भाजपा की कठपुतली बन गया है चुनाव आयोग, वोट चोरी के खिलाफ जयपुर में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन

जयपुर। कांग्रेस ने बुधवार को राजस्थान के जयपुर में वोट चोरी के खिलाफ एक विशाल विरोध प्रदर्शन किया। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट समेत राज्य में पार्टी के शीर्ष नेताओं ने इस रैली में हिस्सा लिया। गहलोत ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से उनके वोट चोरी के आरोप की जांच के लिए हलफनामा मांगने पर चुनाव आयोग की आलोचना की। विरोध मार्च के दौरान गहलोत ने एएनआई से कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, शरद पवार, अखिलेश यादव, इन सभी लोगों ने दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के जरिए पूरे देश में यह संदेश दिया है कि वोट चोरी हो रहे हैं। राहुल गांधी ने भी आंकड़े दिए हैं, और चुनाव आयोग उनसे हलफनामा मांग रहा है।

हमने ऐसा पहली बार देखा है। गहलोत ने कहा कि जो हो रहा है वह लोकतंत्र के लिए खतरनाक है... बिहार में 60 लाख वोट काटे गए, लेकिन एक भी वोट नहीं जोड़ा गया... इसके खिलाफ प्रदेश कांग्रेस कमेटी विरोध प्रदर्शन कर रही है, जिसमें सभी लोग भाग ले रहे हैं। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने आरोप लगाया कि देश की संवैधानिक संस्थाओं को खोखला करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि आज देश भर में वोटों में धांधली को लेकर सवाल उठ रहे हैं... चुनाव आयोग कोई जवाब नहीं दे रहा है... मुझे आश्चर्य है कि भाजपा चुनाव आयोग का बचाव करने के लिए आगे आ रही है। हमारी संवैधानिक संस्थाओं को खोखला करने की कोशिश की जा रही है। इस हफ्ते की शुरुआत में, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसदों ने चुनाव आयोग के मुख्यालय तक मार्च निकाला और चुनावी राज्य बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया से समाज का एक बड़ा वर्ग मताधिकार से वंचित हो जाएगा।

राहुल गांधी के संपर्क में हैं चंद्रबाबू नायडू, पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी ने लगाए गंभीर आरोप

विशाखापत्तनम।

आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम और वाईएसआरसीपी के प्रमुख जगन मोहन रेड्डी ने दावा किया है कि सीएम चंद्रबाबू नायडू तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के जरिए राहुल गांधी के संपर्क में हैं। जगन मोहन रेड्डी ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा और सवाल किया कि राहुल गांधी, वोट चोरी का मुद्दा जोर-शोर से उठा रहे हैं, लेकिन वे आंध्र प्रदेश में वोट चोरी का मुद्दा क्यों नहीं उठा रहे हैं? जगन मोहन रेड्डी ने दावा किया कि इसकी वजह ये है कि राहुल गांधी, चंद्रबाबू नायडू के संपर्क में हैं। जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि, जब राहुल गांधी वोट चोरी की बात करते हैं, तो वे आंध्र प्रदेश के बारे में बयान क्यों नहीं देते? जहां घोषित नतीजों और मतगणना के दिन के नतीजों के बीच 12.5 प्रतिशत वोटों का अंतर रहा। वे अरविंद केजरीवाल के बारे में क्यों नहीं बोलते? जबकि अरविंद केजरीवाल खुद विधायक का चुनाव हार गए थे, लेकिन राहुल गांधी आंध्र प्रदेश के बारे में बात नहीं करते क्योंकि चंद्रबाबू नायडू रेवंत रेड्डी के जरिए हॉटलाइन पर राहुल गांधी के संपर्क में हैं। मैं राहुल गांधी जैसे व्यक्ति पर क्या टिप्पणी करूं, जो खुद अपने काम के प्रति ईमानदार नहीं हैं? जगन मोहन रेड्डी का यह बयान ऐसे समय सामने आया है, जब 3500 करोड़ रुपये के शराब घोटाले में आंध्र प्रदेश पुलिस ने जो आरोपपत्र दायर किया है, उसमें पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी का भी नाम है।

टैरिफ वॉर के बीच पीएम मोदी जाएंगे अमेरिका; ट्रंप संग होगी अहम वार्ता, पाकिस्तान को देंगे मुंहतोड़ जवाब

नई दिल्ली। भारत-अमेरिका संबंधों में टैरिफ वॉर और पाकिस्तान से आती परमाणु धमकियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने अमेरिका का दौरा करने वाले हैं। यह यात्रा न केवल संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत की आवाज बुलंद करने के लिए अहम होगी, बल्कि व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से तनावपूर्ण रिश्तों को संभालने का भी एक मौका होगी। सूत्रों के मुताबिक, पीएम मोदी इस मंच से पाकिस्तान सेना प्रमुख असीम मुनीर की हालिया परमाणु गीदड़भभकी का कड़ा जवाब भी दे सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 80वां सत्र 9 सितंबर से शुरू होगा और उच्च-स्तरीय बहस 23 से 29 सितंबर के बीच चलेगी। प्रस्तावित स्पीकर सूची के अनुसार, पीएम मोदी 26 सितंबर की सुबह सत्र को संबोधित करेंगे। इसी दिन इजराइल, चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के नेता भी भाषण देंगे। ट्रंप 23 सितंबर को मंच से बोलेंगे, जो उनके दूसरे कार्यकाल का पहला ऐसा संबोधन होगा। इस यात्रा का मुख्य मकसद भारत-अमेरिका व्यापार विवाद को सुलझाना और टैरिफ पर किसी समझौते की संभावना तलाशना है। वर्तमान में अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाए हैं। 25% पहले से लागू हैं और अतिरिक्त 25% जल्द लागू होने वाले हैं। भारत ने इन टैरिफ को अनुचित और अविवेकपूर्ण बताते हुए साफ कहा है कि वह किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं करेगा। विदेश मंत्रालय ने भी दो टूक कहा कि भारत अपने आर्थिक और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा।

इस पृष्ठभूमि में, पाकिस्तानी सेना प्रमुख मुनीर का हालिया अमेरिकी दौरा और वहां से दी गई परमाणु हमले की धमकी ने स्थिति को और संवेदनशील बना दिया है। भारत पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि वह न्यूक्लियर ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा और अपनी सुरक्षा के लिए सभी कदम उठाएगा। पीएम मोदी की यह यात्रा न केवल आर्थिक वार्ता बल्कि सुरक्षा और रणनीतिक मुद्दों पर भी निर्णायक साबित हो सकती है।

फतेहपुर में तोड़फोड़ की घटना में भाजपा कार्यकर्ता शामिल, दोषियों को बचा रही योगी सरकारः अखिलेश यादव

लखनऊ।

समाजवादी पार्टी (सपा) प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में एक मजार में तोड़फोड़ की घटना में भाजपा कार्यकर्ताओं के शामिल होने का आरोप लगाया। यादव ने साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर दोषियों को बचाने की कोशिश करने का आरोप भी लगाया। यादव ने कहा कि लोगों को रोजगार चाहिए, सांप्रदायिक राजनीति नहीं। यादव झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि देने यहां आए थे। शिबू सोरेन का हाल में निधन हो गया था। दक्षिणपंथी समूहों के सदस्य सोमवार को मकबरे के परिसर में घुस गए और कब्रों को क्षतिग्रस्त कर दिया। दक्षिणपंथी समूहों के सदस्यों ने दावा किया कि उक्त स्थल एक हिंदू मंदिर स्थल है और वहां पूजा करने की अनुमति मांगी। यादव ने लखनऊ लौटते समय रांची के बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बात करते हुए कहा, (उत्तर प्रदेश) सरकार फतेहपुर की घटना पर क्या कर रही है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इसमें शामिल लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हर कोई जानता है कि वे कौन हैं। वे भाजपा के नेता और कार्यकर्ता हैं। सपा प्रमुख ने आरोप लगाया कि भाजपा हिंदू-मुसलमान के नाम पर नफरत फैलाती है। उन्होंने कहा, ''फतेहपुर की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। वीडियो फुटेज में दिख रहे लोगों को जेल भेजा जाना चाहिए। अगर प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस उन्हें जेल नहीं भेज रहे हैं, तो सरकार को उनके खिलाफ एक फैसला लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि सांप्रदायिक राजनीति देश को नुकसान पहुंचा रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने ब्रिटिश विचारधारा फूट डालो और राज करो को अपना लिया है।

रोडवेज बस और ट्रक की भीषण टक्कर में पांच लोगों की मौत, 15 अन्य घायल

जौनपुर।

जिले के खेतासराय थाना क्षेत्र के गुरैनी पेट्रोल पंप के पास एक रोडवेज बस और ट्रक की आमने-सामने की टक्कर में दो साल की बच्ची समेत पांच लोगों की मौत हो गई और लगभग 15 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि घटना मंगलवार रात खेतासराय थाना क्षेत्र के गुरैनी पेट्रोल पंप के पास हुई। अधिकारियों ने बताया कि दुर्घटना रात करीब साढ़े 10 बजे हुई जब जौनपुर से आ रही बस और शाहगंज से आ रहे एक ट्रक की आपस में टक्कर हो गई। पुलिस अधीक्षक (एसपी) डॉ. कौस्तुभ ने बताया कि मृतकों में दो महिलाएं, दो पुरुष और एक बच्चा शामिल है। पुलिस के अनुसार, इस घटना में 15 अन्य घायल हुए हैं।

सीएम योगी ने की तिरंगा यात्रा की शुरुआत, दोनों डिप्टी सीएम के साथ ली सेल्फी

लखनऊ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास से तिरंगा यात्रा की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव मौर्या के साथ सेल्फी खींचकर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम में दोनों डिप्टी सीएम विशेष रूप से मौजूद रहे। सीएम योगी ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना किया। इस तिरंगा यात्रा में कई स्कूलों के बच्चे भी शामिल हुए।

बकवास मत करो, हमारे पास है ब्रह्मोस, सिंधु जल समझौते पर शहबाज शरीफ के बयान से भड़के असदुद्दीन ओवैसी

नई दिल्ली। सिंधु जल संधि स्थगित होने के बाद से पाकिस्तान लगातार पानी के लिए गिड़गिड़ा रहा है. पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने कहा कि दुश्मन (भारत) पाकिस्तान से एक बूंद पानी भी नहीं छीन सकता. इस पर हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने उन्हें करारा जवाब दिया है. ओवैसी ने कहा कि हमारे पास ब्रह्मोस है उन्हें ऐसी बकवास नहीं करनी चाहिए. उन्होंने कहा, अब बहुत हो गया. भारत पर ऐसी धमकियों का कोई असर नहीं होगा. पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच पर ओवैसी ने कहा, मैं क्रिकेट मैच देखने नहीं जा रहा हूं. मेरी अंतरात्मा, मेरा दिल इसकी इजाजत नहीं देता. हमें उस देश के लोगों के साथ क्रिकेट क्यों खेलना है जो हमें हर दिन धमकी दे रहे हैं?

पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकी हमले के एक दिन बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई दंडात्मक कदम उठाए, जिनमें 1960 की सिंधु जल संधि को स्थगित करना भी शामिल था.पाकिस्तान ने बार-बार चेतावनी दी है कि पानी रोकने के लिए किसी भी हस्तक्षेप को युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा. पाक पीएम शहबाज शरीफ ने कहा, मैं आज दुश्मन को बताना चाहता हूं कि अगर आप हमारा पानी रोकने की धमकी देते हैं तो यह बात ध्यान में रखें कि आप पाकिस्तान के पानी की एक बूंद भी नहीं छीन सकते. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर भारत ने ऐसी कोई कार्रवाई की तो आपको फिर ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि आपको पछताना पड़ेगा. एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने अमेरिका की ओर से भारत पर लगाए गए 50 फीसदी टैरिफ पर टिप्पणी की. उन्होंने कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यह तय करना होगा कि वे उस देश के साथ व्यापार करेंगे जहां आतंकवाद एक व्यापार है या भारत के साथ जो एक रणनीतिक सहयोगी रहा है. ट्रंप कौन होते हैं ये कहने वाले कि हमें तेल नहीं खरीदना चाहिए. नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से एक राजनीतिक बयान आना चाहिए था, लेकिन विदेश मंत्रालय की ओर से केवल एक बयान आया.

बिहार में जिंदा मिले मुर्दे! कई लोगों के घर बदले, नई वोटर लिस्ट में भारी गड़बड़ी

चंद्रमंडी (जमुई)। प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर इन दिनों भाकपा माले प्रखंड टीम लगातार प्रखंड के पंचायतों का दौरा कर मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम के बाद हुए कार्यों का भौतिक सत्यापन कर रही है। ठाढ़ी पंचायत के बूथ संख्या 233 और बूथ संख्या 234 के निरीक्षण के दौरान टीम को कई प्रकार की अनियमितताएं मिलीं। भाकपा माले नेता मनोज पांडेय ने बताया कि बाघटांड़ गांव के पूर्वी भाग के बूथ संख्या 233 का दौरा किया गया। पार्टी जिला कमेटी सदस्य राहुल कुमार यादव मेरे साथ थे। गांव पहुंचकर जांच के दौरान पाया गया कि

मतदाता संख्या 651 भदी नैया की मृत्यु पांच वर्ष पूर्व, प्यारे नैया मतदाता संख्या 798 की मृत्यु चार वर्ष पूर्व तथा मटरू नैया मतदाता संख्या 753 की मृत्यु एक वर्ष पूर्व हो गई थी। इनके नाम अभी भी मतदाता सूची में दर्ज हैं। वहीं मतदान केंद्र संख्या 10 पर भी मतदाता सूची में नाम दर्ज है। 234 मध्य विद्यालय ठाढ़ी पश्चिमी भाग ग्राम सिझुआ के मतदाता सुखरमुनी हांसदा, विजय यादव की पत्नी इंदु देवी, सबीना टुडू, अभय यादव की पत्नी पूजा कुमारी, राजेश हांसदा, भरत हांसदा सभी का मकान नंबर 00 है. सोमरा सोरेन, विजय यादव, पवन कुमार पिता राजेंद्र यादव, सीताराम कुमार पिता लालमोहन यादव सभी का मकान नंबर 01 है। लालमोहन यादव की पत्नी सुमा देवी, श्याम लाल हेम्ब्रम, आरती मुर्मू, शिबू हेम्ब्रम सभी का मकान नंबर 01 है. 05. भैया हेम्ब्रम, धर्मेंद्र यादव, कुसुमलता हेम्ब्रम, रिंकू देवी पति नरेश राय, नारायण राय सभी का मकान नम्बर 06 है। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि वोटर लिस्ट में उन लोगों के नाम भी शामिल हैं जिनकी कई साल पहले मौत हो चुकी है. भाकपा(माले) ने मतदाता पुनरीक्षण सूची में गड़बड़ी करने वाले सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जांच लगातार चल रही है।

उरी में गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा इलाका... सेना का एक जवान शहीद

उरी, कश्मीर।

जम्मू कश्मीर के उरी में एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिश की गई है, जिसे समय पर ही नाकाम कर दिया गया है। अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि बुधवार (13 अगस्त, 2025) को जम्मू-कश्मीर के उरी सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर सेना ने घुसपैठ की एक कोशिश नाकाम कर दी, जिसमें एक भी जवान शहीद हो गया है। उन्होंने बताया कि सैनिकों ने उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के उरी के चुरुंडा इलाके में घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी है। हालांकि, अधिकारियों ने बताया कि गोलीबारी के दौरान सेना का एक जवान शहीद हो गया है। अधिकारियों ने बताया कि ऑपरेशन जारी है और आगे की जानकारी का इंतजार है।

सोनिया भारतीय नागरिक बनने से पहले वोटर बनीं- भाजपा

वोट चोरी पर संग्रामः अनुराग बोले- रायबरेली में एक पते पर 47 वोटर्स, राहुल को ये कभी नहीं दिखे

नई दिल्ली। कांग्रेस के वोट चोरी के आरोपों का भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने पलटवार किया है. बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के तमाम आरोपों को लेकर दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान उन्होंने कहा कि हर हार के बाद कांग्रेस नया बहाना ढूंढती है. ईवीएम और चुनाव आयोग से लेकर हर संवैधानिक संस्था पर आरोप लगाए जाते हैं. बिहार चुनाव पास देख कांग्रेस फिर यही कर रही है. अनुराग ठाकुर ने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस आयोग पर सवाल उठा रही है उससे ये तो साफ है कि वो साफ तौर पर देश की जनता अपमान कर रही है. कांग्रेस देश को वोटरों को नीचा दिखा रही है. हारते ये हैं और इल्जाम चुनाव आयोग और बीजेपी पर लगा देते हैं. इनकी हालत वैसी है कि धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करते रहे. अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुनाव हरवाया. और चुनावी भ्रष्टाचार की नींव कांग्रेस ने 1952 में ही रख दी थी. कांग्रेस ने सीपीआई के साथ मिलकर आंबेडकर को हराया था. रिकॉर्ड में है कि 74,333 वोट उस दौरान खारिज किए गए थे जबकि डॉ. आंबेडकर मात्र 14,561 वोट से हारे थे. कांग्रेस ने तो संविधान निर्माता और दलित नेता को पहले चुनाव में ही निपटाने की कोशिश की. 31 अप्रैल 1952 को आंबेडकर ने 18 पेज की याचिका दी थी. संविधान निर्माता को चुनावी भ्रष्टाचार से हराया गया.

रायबरेली के आंकड़े दिए

अनुराग ठाकुर ने इस दौरान रायबरेली के आंकड़े गिनाए. उन्होंने कहा कि एक ही घर में 47 डुप्लिकेट वोटर हैं. मोहम्मद कैफ खान नाम से बूथ 83, बूथ 151

और बूथ 218 पर वोटर लिस्ट में नाम है. रायबरेली में 47 वोटर आईडी मकान नंबर 189 के पोलिंग बूथ 131 पर रजिस्टर हैं. उनके नाम मोहम्मद इस्लाम, मोहम्मद कासिम, साफिया आदि हैं. ऐसा ही कुछ हाल पश्चिम बंगाल में भी है, जहां डायमंड हार्बर लोकसभा सीट पर मकान नंबर 0011 पर कई मतदाता रजिस्टर हैं कांग्रेस चुनाव आयोग को भी चोरी करने का काम करती थी. 2005

अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुनाव हरवाया. और चुनावी भ्रष्टाचार की नींव कांग्रेस ने 1952 में ही रख दी थी.

में खबर छपी की नवीन चावला को सोनिया गांधी ने चुनाव आयुक्त नियुक्त किया. उस समय पीएम मनमोहन सिंह थे. चीफ इलेक्शन कमिश्नर गोपाल स्वामी ने इसकी लिखित शिकायत की थी कि नवीन चावला ने बाहर जाकर फोन पर सोनिया से बात कर खबर लीक करने का काम किया है. चुनाव आयुक्त आरके त्रिवेदी कांग्रेस में शामिल हुए और गुजरात के गवर्नर बने.रमा देवी हिमाचल प्रदेश की गवर्नर बनीं. लिंगदोह भी कांग्रेस में शामिल हुए.टीएन शेषन भी कांग्रेस में शामिल हुए और चुनाव लड़े और हार गए,

उन्होंने कहा कि कांग्रेस, चुनाव आयोग को ही चोरी करने का काम करती थी. 2005 में खबर छपी कि नवीन चावला को सोनिया गांधी ने चुनाव आयुक्त नियुक्त किया, जबकि उस समय पीएम मनमोहन सिंह थे. चुनाव आयुक्त आरके त्रिवेदी कांग्रेस में शामिल हुए और गुजरात के गवर्नर बने. रमा देवी हिमाचल प्रदेश की गवर्नर बनीं. लिंगदोह भी कांग्रेस में शामिल हुए. टीएन शेषन भी कांग्रेस में शामिल हुए और चुनाव लड़े और हार गए. वहीं, बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से इतर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर दावा किया कि सोनिया गांधी का वोटर आईडी कार्ड उन्हें देश का नागरिकता मिलने से पहले ही मिल गया था. उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी का वोटर कार्ड भारत की नागरिकता लेने से पहले ही बनाया जा चुका था. अनुराग ठाकुर ने कहा कि सोनिया गांधी का नाम 1980 में वोटर लिस्ट में शामिल हुआ और उन्हें नागरिकता 1983 में मिली.